Government have accepted the recommendations of the Pillai Committee Report on standardisation of Pay scales, allowances and perquisites of Officers of the nationalised banks with certain modifications suggested by the Group of Bankers who were asked by the Government to suggest the manner in which recommendations of the Pillai Committee should be implemented. Nataionalised banks were advised to initiate necessary steps for the implementation of these recommendations as accepted by Government.

All India Confederation of Bank Officers Organisations, however, protested against the implementation of Pillai Committee Scheme. Government have held consultations with the concerned parties and it has been agreed that Indian Banks' Association will hold further talks with the representatives of All India Confederation of Bank Officers' Organisations on the list of specific points already submitted by them to the Indian Banks Association.

(c) The discussions between Indian Banks Association and All India Confederation of Bank Officers Organisations are under way and the Government expects to implement at an early date the Scheme with such modifications as become necessary.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में नालन्दा जिले में शिक्षित बेरोजगारों को दिया गया ऋण

1841. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने मार्च, 1977 से जून 1978 तक बिहार राज्य में नालन्दा जिले में एक-नियोजन के लिये कितने शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिया और कुल कितना ऋण दिया गया ?

1846 LS.—

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 1977 और जनवरी, 1978 की अवधि के दौरान बिहार के नालंदा जिले के 50 बेरोजगार स्नातकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण दिये गये थे । जनवरी, 1978 के अन्त की स्थिति के अनुसार बकाया राशि 11.75 लाख रुपये थी ।

फलों और फल उत्पादों का निर्यात

1842. श्री राम सेवक हजारी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान किन-किन फलों और फल उत्पादों का निर्यात किया गया और इसके परिणाम स्वरूप सरकार को कितनी आय हुई ;

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में आय में वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1977-78 के दौरान जिन फलों तथा फल उत्पादों का निर्यात किया गया, वे मुख्यत: थे—सन्तरे, नीबू, खट्टे नींबू, अंगूर, केले, सेब, नाशपाती, सेपोटा, अनन्नास, खजूर, आम, इमली, खुमानी, मुरब्बे, जैली तथा फलों के रस । इन मदों के निर्यात से सरकार को कोई आय नहीं होती है । अप्रैल, नवम्बर, 1977 के दौरान निर्यातित फलों तथा फल-उत्पादों का कुल एफ ओ बी मूल्य 12.11 करोड़ रु० था ।